गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

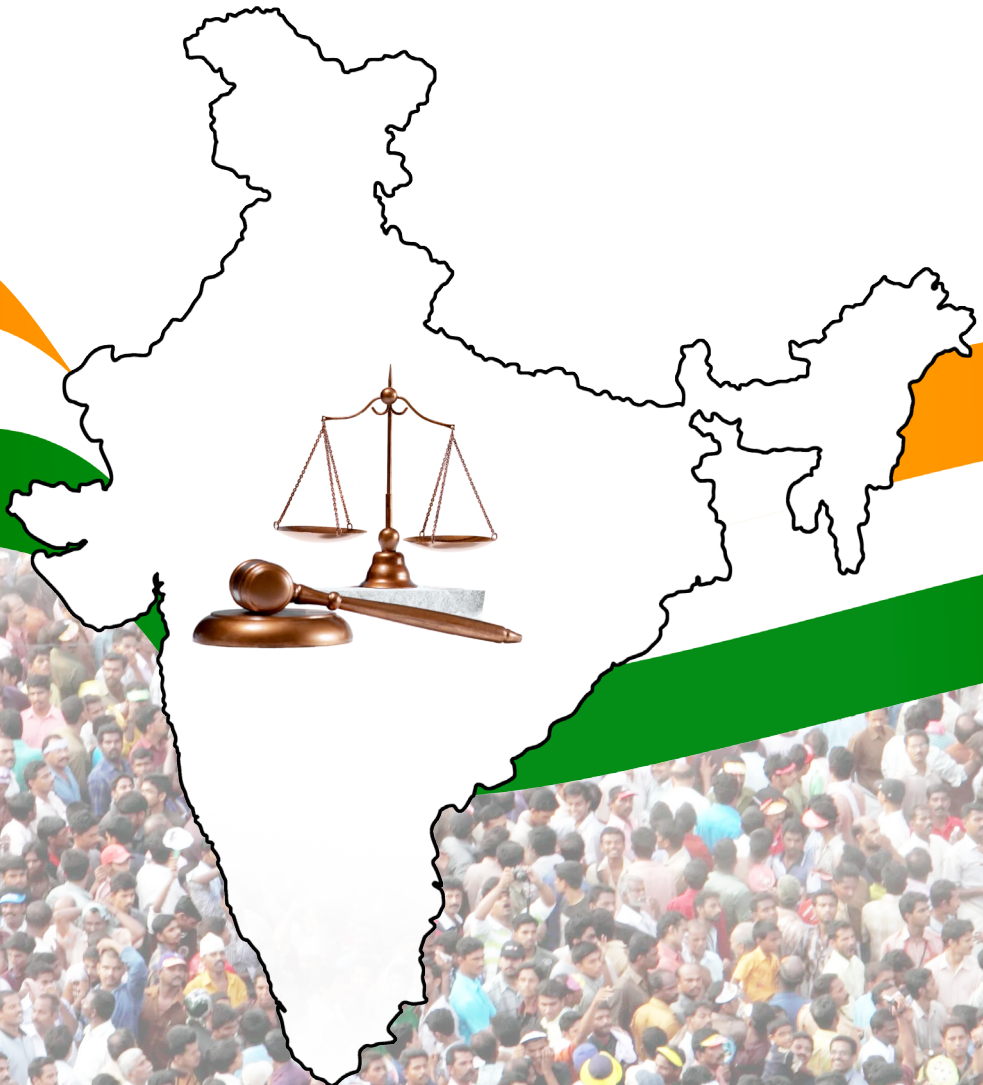

New Criminal Laws 2023

Collaborative Transformation: Stakeholder-Driven Reforms

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

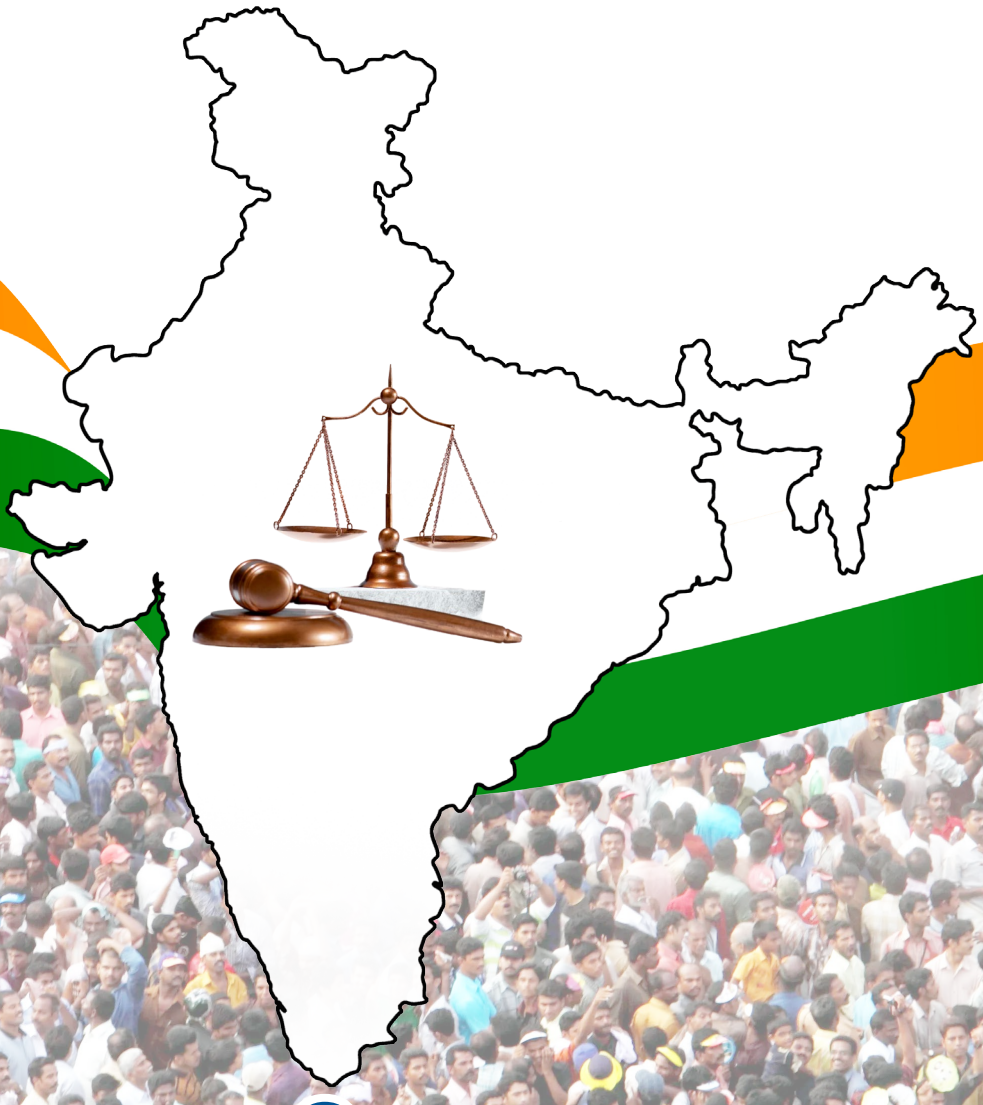

नए आपराधिक कानून 2023

सहयोगात्मक परिवर्तन: हितधारक-संचालित सुधार

Objectives

1. **Constitutional Justice:** Aligning with the vision of the Indian Constitution.
2. **Justice-centric System:** Shift from being punishment-centric to justice-centric.
3. **Shedding Colonial Mindset:** By fulfilling the 'Panch Pran' pledge.
4. **Victim-centric Justice:** Prioritising the rights and needs of victims.
5. **Accessible Justice:** Ensuring affordability, accessibility, and simplicity.
6. **Transparency and Accountability:** Making procedures consistent and transparent.

Aim

- **Fair and Time-bound Investigation:** Ensuring evidence-based speedy trials.
- **Court and Prison Burden Reduction:** Streamlining the legal process for releasing undertrials on bail, reducing incarceration by introducing community service.

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

लक्ष्य

1. **संवैधानिक न्याय**: भारतीय संविधान की दृष्टि के अनुरूप।
2. **न्याय-केंद्रित प्रणाली**: दंड-केंद्रित से न्याय-केंद्रित की ओर बढ़ना।
3. **गुलामी की मानसिकता को समाप्त करना**: 'पंच प्रण' का संकल्प पूरा करना।
4. **पीड़ित-केंद्रित न्याय**: पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देना।
5. **सुलभ न्याय**: सामर्थ्य, पहुंच और सरलता सुनिश्चित करना।
6. **पारदर्शिता और जवाबदेही**: प्रक्रियाओं को सुसंगत और पारदर्शी बनाना।

उद्देश्य

- **निष्पक्ष और समयबद्ध जांच**: साक्ष्य-आधारित त्वरित ट्रायल सुनिश्चित करना।
- **न्यायालय और जेल के बोझ में कमी**: विचाराधीन कैदीयों को जमानत पर रिहा करने और कारावास की अवधि को कम करने के लिए सामूदायिक सेवा का प्रावधान।
- **दोषसिद्धि दर में वृद्धि**: तकनीक के उपयोग तथा प्रक्रियाओं एवं कार्यवाहियों की समयबद्ध तरीके से निस्तारण से न्याय देने की कुशलता में वृद्धि।

- **Increased Conviction Rate:** Enhancing the effectiveness of justice delivery by imbibing technology and timebound completion of processes and proceedings.

Consultative Process

- **Initiated in 2019:** Comprehensive review of criminal laws.
- **Stakeholder Involvement:** Consultations with Governors, CMs, Judges, MPs, IPS officers and more.
- **Committee Formation:** Chaired by Vice-Chancellor, National Law University, Delhi.
- **Suggestions Received:** 3,200 from various stakeholders.
- **Hon'ble Home Minister's Efforts:** Over 150 meetings held to deliberate on the suggestions.

परामर्शात्मक प्रक्रिया

- 2019 में शुरूआत : आपराधिक कानूनों की व्यापक समीक्षा।
- हितधारकों की भागीदारी : राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, न्यायाधीशों, सांसदों, आईपीएस अधिकारियों और अन्य के साथ परामर्श।
- समिति का गठन : अध्यक्षता–कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली ।
- सुझाव : विभिन्न हितधारकों से 3200 सुझाव प्राप्त हुए।
- माननीय गृह मंत्री के प्रयास : प्राप्त सुझावों पर विचार–विमर्श के लिए 150 से अधिक बैठकें आयोजित की गईं।